जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 70 प्रभात चूरू, रविवार 7 जुलाई, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

काफी रोचक रहेगा जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव इस बार

भाजपा अपने घोषणा पत्र में वादा कर रही है कि, पाकिस्तान से पी.ओ.के. (पाक अधिकृत कश्मीर) वापस लेगी

- श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जुलाई। जम्मू व कश्मीर के आगामी विधान सभा चुनावों में भाजपा अपने चुनावी घोषणापत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले भाग “पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर” को “वापस अपने कब्जे” में लेने का वादा शामिल कर सकती है।

केन्द्र सरकार को लगता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 30 सितम्बर की मियाद तक देश के उत्तरी राज्यों में चुनाव कराने के आदेश का सम्मान करने को तैयार है। पिछले साल 11 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने देश के चुनाव को 30 सितम्बर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उम्मीद की जाती है कि चुनाव आयोग वर्तमान में चल रही अमरनाथ यात्रा के 19 अगस्त को समाप्त होने के बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा।

कुछ समय पहले एक साक्षात्कार गृहमंत्री अमित शाह ने 30 सितम्बर तक इस वर्ष वादा किया था और चुनाव कराने का और इसके बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। वर्ष 2019 में, जम्मू व कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था और इसको केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया था। अभी हाल ही में भाजपा की तरफ से जम्मू व कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को तीव्र गति से बढ़ाया गया है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी जी. किशन रेड्डी व प्रभारी तरुण चुघ ने हाल ही में जम्मू में राज्य के भाजपा नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर बैठक की थी।

- लग रहा है कि, भाजपा गंभीर है कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में 30 सितम्बर से पहले जे. एण्ड के. में विधानसभा चुनाव संपूर्ण हो जायें।
- ऐसा लग रहा है कि, 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाने के बाद, चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जायेगा। इस बार जे. एण्ड के. विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 114 कर दी गईं, इनमें 24 सीटें पी.ओ.के. (पाक अधिकृत कश्मीर) में हैं।
- चुनाव की तैयारी में जे. एण्ड के. के भाजपा के प्रभारी किशन रेड्डी और तरूण चुग ने रणनीति तैयार करने के लिये प्रदेशाध्यक्ष से मंत्रणा शुरु कर दी है तथा नड्डा भी श्रीनगर जा रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने।
- पी.डी.पी. की महबूबा मुफ्ती की हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अनंतनाग-रजौरी में तथा उमर अब्बदुल्लाह की अपनी लोकसभा सीट पर पराजय से भाजपा काफी उत्साहित है।

इस बीच, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा शनिवार को जम्मू के दौरे पर गए, जहां वे प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी समिति की बैठक को सम्बोधित करेंगे।

भाजपा जम्मू व कश्मीर में चुनावों से पूर्व कोई गठबंधन किए बगैर विधानसभा की 90 सीटों पर अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है परन्तु संभावना है कि चुनावों के पश्चात “समान विचारधारा वाली पार्टियों” के साथ गठबंधन अस्तित्व में आ सकता है।

इस सप्ताह के पूर्वार्ध में, भाजपा के वरिष्ठ नेता जे.पी.नड्डा व अमित शाह ने प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा की थी और इसके साथ ही उन्हें चुनावों के लिए “तैयार रहने” का निर्देश दिया था। संयोगवश, राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है इनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय बजट 23 जुलाई को पेश होगा

नई दिल्ली, 6 जुलाई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। तारीखों की घोषणा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की।

रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिये बताया कि बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त के बीच आयोजित होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश करेंगी। उन्होंने 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया था। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त की गईं सीतारमण लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली शख्सियत बन जाएंगी। वह मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगी जिन्होंने लगातार छह बजट पेश किए थे। बता दें कि आम चुनाव 2024 के बाद 24 जून से संसद का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यपाल व विधानसभा स्पीकर के बीच अहम् की लड़ाई हास्यास्पद स्थिति तक पहुंची

उपचुनाव जीतकर आए दो नये विधायकों को शपथ कौन दिलायेगा, इसका हल संविधान तथा विधानसभा की परम्पराओं के बीच लटकता रहा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जुलाई। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) और राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के बीच चल रहा विवाद टी.एम.सी. के दो और विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद आज और गहरा गया। राज्य विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी द्वारा सयंतिका बनर्जी और रेवात हुसैन सरकार को विधायक पद की शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना की।

सयंतिका बनर्जी और सरकार क्रमशः बड़ानगर और भगवानगोला निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रों से उपचुनाव जीते थे। इन उपचुनावों के नतीजे गत 5 जून को घोषित हुए थे। इनका शपथ ग्रहण तभी से लम्बित था, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल और राज्यपाल कार्यालय के कारण इस पर सभी का फोकस था। स्पीकर बिमान बनर्जी ने अन्ततः उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद तृणमूल के विधायकों ने सदन में “जय बांग्ला” के नारे लगाए।

- मतगणना के बाद, रिज़ल्ट घोषित हो गया था, पर, राज्यपाल ने व्यवस्था दी कि दोनों नये विधायक उनके निवास पर आकर शपथ ग्रहण करें तथा शपथ दिलाने की जिम्मेवारी राज्यपाल ने डिप्टी स्पीकर को दी।
- विधानसभाध्यक्ष ने राज्यपाल को नीचा दिखाने की दृष्टि से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर स्वयं नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला दी।
- विधानसभाध्यक्ष ने दलील दी कि, विधानसभा केवल रूल्स से ही नहीं, संविधान के अनुसार चलती है।
- चर्चा है कि, शायद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाये।

तथापि, उसके बाद राज्यपाल बोस ने कहा कि राज्यपाल के दफ्तर द्वारा उनके अधीनस्थ आशीष बनर्जी की नियुक्ति किए जाने के बावजूद स्पीकर ने शपथ दिलवाकर संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। फिर भी, आशीष बनर्जी ने यह उल्लेख कर ऐसा करने से इंकार किया कि स्पीकर द्वारा शपथ दिलाये जाने के पूर्व उदाहरण मौजूद हैं।

बोस ने कहा है कि “स्पीकर द्वारा दो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाये जाने से हुई संवैधानिक अनीति को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।’ बोस ने सोशल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने भेजेगी तेलंगाना सरकार

मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी ने अल्पसंख्यकों के लिए एक कल्याणकारी योजना घोषित की है

- लक्ष्मण वैंकट कुची -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जुलाई। तेलंगाना में रेवन्त रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों के लिये एक रूटीन कल्याणकारी योजना लेकर आई है जिसे लेकर विपक्षी भाजपा इसे “अल्पसंख्यक तुष्टीकरण” बताते हुये, जबरदस्त प्रहार कर सकती है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की “ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम” के तहत, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से विदेश में अध्ययन करने में सहयोग/सहायता के लिये आवेदन पत्र मांगे हैं। यह योजना के चन्द्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार ने 2015 में आरम्भ की थी।

19 मई, 2015 को राज्य सरकार ने एक विस्तृत गवर्नमैंट ऑर्डर एमएस नं. 24 के तहत यह योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य विदेशों में उच्च अध्ययन के लिये अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सहयोग देना था। यह योजना अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस तथा न्यूजीलैंड के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट तथा पी.एचडी. कोर्स करने में पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की मदद करती है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित उम्मीदवारों को 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति या वास्तविक ट्यूशन फीस, जो भी कम हो, प्रदान किए जाते हैं।

- यह योजना मई 2015 में तात्कालीन मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने घोषित की थी जिसके तहत अल्पसंख्यकों को विदेशों में पढ़ने के लिए 20 लाख रूपए तक की सहायता दी जाती है।
- राज्य सरकार ने कहा है कि, छात्रवृत्ति के लिए 8 जुलाई से 7 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा।
- राज्य सरकार के इस फैसले ने भाजपा को कांग्रेस पर “मुस्लिम तुष्टीकरण” का आरोप लगाने का मौका दे दिया है।

राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि ‘स्प्रिंग ऑफ 2024’ के लिये आवेदन पत्र स्वीकार किए जायेंगे। अधिसूचना के अनुसार आवेदन खिड़की 8 जुलाई से 7 अगस्त तक खुली रहेगी तथा जिन पात्र विद्यार्थियों ने 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है, उन्हें आवेदन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

वस्तुतः राज्य सरकार केवल अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की ही मदद नहीं कर रही है, बल्कि विदेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका में आज़ादी के जश्न में गोलीबारी, 33 मरे

कैलिफॉर्निया, 6 जुलाई। अमेरिका में हर साल की तरह इस बार भी 4 जुलाई को लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में गोलीबारी और हिंसा की घटनाओं में 33 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 11 लोग शिकागो में मारे गए।

- अमेरिका में चार जुलाई को आयोजित “इंडिपैंडैंस डे” समारोहों में देश भर में कई जगहों पर नागरिको द्वारा गोलियां चलाने की घटनाएं सामने आईं।

शिकागो सनटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिकागो में गोलीबारी में 11 लोग मारे गए और 55 अन्य घायल हो गए। इसमें दो महिलाएं और एक 8 वर्षीय लड़का शामिल है। उधर, कैलिफोर्निया के हंटिंगटन बीच में स्वतंत्रता दिवस पर आतिशबाजी शो खत्म होने के दो घंटे बाद एक हमले में दो लोग मारे गए। उधर, क्लीवलैंड में एक 10 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना में रैवन्त रेड्डी ने के.सी.आर. को दिखाया “जैसी करनी वैसी भरनी”

तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री के.सी.आर. ने कांग्रेस के साथ जो किया अब रैवन्त रेड्डी बी.आर.एस. के साथ वही कर रहे हैं

- लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जुलाई। जानी-मानी कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार उससे बदले में पाओगे, और यह बात बिलकुल पक्की है खास तौर से राजनीति में।

तेलंगाना के पूर्व शक्तिशाली मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने जो व्यवहार पूर्व में कांग्रेस के साथ किया था आज वही उनको तकलीफ दे रहा है।

पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी और इस दल को तोड़कर एक छोटे से समूह में बदल दिया था और इस प्रकार विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या बढ़ाकर राज किया तथा संसद के चुनावों में भी उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। चुनावों में कांग्रेस के जो विधायक निर्वाचित हुए थे उन्हें कांग्रेस से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और एक बार स्थिति ऐसी बन गई मानों तेलंगाना प्रदेश में केवल दो ही पार्टियां रह गई हों।

- बी.आर.एस. के राज्यसभा सदस्य केशव राव एवं बी.आर.एस. के विधायकों को रैवन्त रेड्डी पहले ही कांग्रेस में शामिल कर चुके हैं और हाल ही में इसी पार्टी के दस विधान परिषद सदस्यों को भी रेड्डी ने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है।
- बी.आर.एस. के वर्किंग प्रैसिडैंट के.टी. रामाराव ने इस दलबदल को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि, कांग्रेस ने अपने मैनिफैस्टो “न्याय पत्र” में दल-बदल रोकने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन की बात कही है। क्या यही है कांग्रेस का न्याय पत्र?
- ज्ञातव्य है कि, जब के.सी.आर. मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को तोड़ा, यहां तक कि, प्रदेश में कांग्रेस एक छोटा सा समूह बनकर रह गई थी। राज्य में दो ही पार्टियाँ बची थीं सत्तारूढ़ बी.आर.एस. और विपक्षी भाजपा।
- पर, जैसे ही रैवन्त रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस की कमान संभाली तो हालात बदलने लगे। वे एक-एक कर न केवल कांग्रेसियों को वापस लाए बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बी.आर.एस. में भारी तोड़-फोड़ मचा दी है।

सत्ताधारी बी.आर.एस. तथा अपने को मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में पेश कर रही भाजपा और कांग्रेस के लोग बी.आर.एस. व भाजपा में चले गए थे।

जब तक रैवन्त रेड्डी ने कांग्रेस की कमान नहीं संभाली थी यही स्थिति थी। रेड्डी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बनते ही पार्टी का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया और अपनी पार्टी के पुराने साथियों को वापस पार्टी में लाना शुरू कर दिया।

के.सी.आर. को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने के बाद, रेवन्त रेड्डी ने चुपचाप पार्टी के पुराने सहयोगियों को मनाकर वापस लाने का कार्यक्रम शुरू किया और अब वे बी.आर.एस. के नेताओं को तोड़ रहे हैं। बी.आर.एस. के एक वरिष्ठ नेता के. केशव राव के पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कश्मीर में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में चार आतंकवादी मारे गये

श्रीनगर, 6 जुलाई (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को दो अलग-अलग मुठभेड़ों में चार आतंकवादी मारे गए और एक सैनिक शहीद हो गया।

- यह मुठभेड़ ऐसे समय पर हुई है जब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है। मुठभेड़ में एक भारतीय सैनिक शहीद हो गया।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुलगाम में दो मुठभेड़ें ऐसे समय में हुई हैं जब अनंतनाग जिले में नुनवान-पहलगाम मार्ग और गंदेरबल जिले में बालटाल मार्ग से पिछले शनिवार को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के कारण पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दोनों मार्गों से तीर्थयात्रियों को कुलगाम जिले से होकर गुजरना पड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि पहली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत राज में राज्य भंडारण निगम द्वारा अरबों रु. का घोटाला करने का आरोप लगाया डॉ. किरोड़ीलाल ने

डॉ. मीणा ने 21 जनवरी 2024 की सी.ए.जी. रिपोर्ट का हवाला देते हुए मु.मंत्री भजनलाल को गत 16 मई 2024 को लिखित शिकायत करते हुए इस घोटाले की जांच करवाने, टैंडर निरस्त करने और दोषी बड़े अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की थी

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 6 जुलाई। कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार में राजस्थान राज्य भंडारण निगम द्वारा कल्पतरू समूह की कंपनी श्री शुभम लॉजिस्टिक लि. को टैंडर देने की आड़ में अरबों रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया है।

डॉ. किरोड़ीलाल ने 21 जनवरी 2024 की सी.ए.जी. की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गत 16 मई 2024 को शिकायती पत्र लिखते हुए इस घोटाले की जांच करवाने, टैंडर निरस्त करने और दोषी बड़े अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की।

राजनैतिक गलियारों में डॉ. किरोड़ीलाल मीणा द्वारा अचानक इस्तीफा देने को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि, मंत्री किरोड़ीलाल ने अपना इस्तीफा इसलिए दिया है, कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार में हुए अरबों रुपये के घोटाले उजागर करने के बाद भी मौजूदा भाजपा सरकार इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है।

दूसरी चर्चा यह भी है कि, डॉ. किरोड़ीलाल ने अपना इस्तीफा इसलिए भी दिया है कि, उनके प्रभाव क्षेत्र में भाजपा ने लोकसभा चुनाव-2024 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। किरोड़ीलाल स्वयं भी चुनाव के दौरान व बाद में भी कई बार कह चुके थे कि, अगर उनके क्षेत्र से भाजपा ने जीत दर्ज नहीं की तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।

- किरोड़ीलाल के आरोप थे कि, जून-2020 में राजस्थान राज्य भंडारण निगम ने गोदाम निर्माण, गोदामों को पी.पी.पी. मोड पर देने और उनका प्रबंधन करने के लिए श्री शुभम लॉजिस्टिक लि. और ऑरिगो कंपनी के साथ एम.ओ.यू. किया था। तथापि, शर्तों की पालना नहीं करने के बावजूद कंपनी से 120 करोड़ रु. की पैनल्टी नहीं वसूली गई।
- सी.ए.जी. की रिपोर्ट में भी भंडारण निगम के अधिकारियों द्वारा इन दोनों कंपनियों पर मेहरबानी दिखाने और उन्हें करोड़ों रु. का फायदा पहुंचाने की बात कही गई है, जिससे किरोड़ीलाल के आरोप सत्यापति होते हैं। लेखाकारों ने बैंक गारंटी, कंपनी से पैनल्टी वसूली व अन्य प्रकरणों को लेकर जब विभाग से जवाब मांगा तो हर बार असंतोषजनक जवाब पाया।
- ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर्स ने कई गंभीर गलतियां पकड़ीं, जिसमें श्री शुभम लॉजिस्टिक व ऑरिगो कंपनी को नाजायज लाभ पहुंचाने का प्रयास स्पष्ट हुआ है। स्टेट वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन इन आपत्तियों में से एक का भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

परन्तु इस घटनाक्रम के बीच, किरोड़ीलाल ने पिछली सरकार के जो घोटाले उजागर करने का दावा किया था, क्या वह पूर्णतः काल्पनिक थे अथवा उनमें कोई बड़ी सच्चाई थी?

किरोड़ीलाल मीणा ने गत 16 मई 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो पत्र लिखा था, उसमें 21 जनवरी 2024 को वरिष्ठ उपलेखाकार संजीव सुराणा की ओर से राज्य सरकार को भेजी गई सी.ए.जी. रिपोर्ट का हवाला दिया था। किरोड़ीलाल के आरोप थे कि, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जून-2020 में राजस्थान राज्य भंडारण निगम ने गोदाम निर्माण, गोदामों को पी.पी.पी. मोड पर देने और उनका प्रबंधन करने के लिए श्री शुभम लॉजिस्टिक लि. और ऑरिगो कंपनी के साथ एम.ओ.यू. किया था।

इस अनुबंध के मुताबिक गोदामों की वार्षिक उपयोगिता 70 प्रतिशत से कम रहने पर नुकसान की भरपाई इन दोनों कंपनियों से की जानी थी। किरोड़ीलाल का कहना है कि, वर्ष 2023-24 में डिफैक्ट की यह रकम करीब 120 करोड़ रु. वसूली जानी है। इसके बावजूद भंडारण निगम ने यह वसूली कंपनी से नहीं की, उल्टा श्री शुभम लॉजिस्टक कंपनी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया और अब कुछ अधिकारी अदालत में राज्य सरकार के पक्ष में कमजोर पैरवी कर रहे हैं।

किरोड़ीलाल मीणा का आरोप था कि, एम.ओ.यू. की शर्तों के मुताबिक कंपनी द्वारा किराये पर लिए जाने वाले गोदाम भी भंडारण निगम के माने जाएंगे, इससे निगम को किराये की 70 फीसदी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)